

परविहन के लिये एक केंद्रीय नकियाय के गठन पर वचिार

संदर्भ

परधानमंत्रि कार्यालय ने यह संकेत दिया है कि केंद्र ने परविहन संबंधी (जनिमें वमिानन, रेलवे, भूतल और जलमार्ग शामिल हैं) सभी मामलों के लिये एक केन्द्रीय नकियाय के गठन पर वचिार-वमिर्श करना प्रारंभ कर दिया है।

परमुख बदि

- अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित 'लॉजिस्टिक्स और एकीकृत परविहन बोर्ड' (Logistics and Integrated Transport Board) आरंभ में भारत की कुशल बहुरूपी परविहन प्रणाली को सुगम बनाने के लिये अंतर-मंत्रिस्तरीय समन्वय को सुधारने का कार्य करेगा।
- इस 'अम्बरेला' (umbrella) नकियाय (जसिकी अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अथवा भारत सरकार के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी) में वति, वाणजिय एवं उद्योग, वदिश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परमुख अधिकारीगण और परतसिपर्द्धात्मक पहलुओं को संबोधित करने के लिये भारतीय उद्योगों के परतनिधि और वधि विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

केंद्रीय नकियाय के गठन का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य अधिक कारोबारी सुगम्यता और भारत के आंतरिक और बाह्य व्यापार को सुनिश्चित करने के लिये वमिानन, रेलवे, भूतल परविहन और नौवहन मंत्रालयों का वलिय कर धीरे-धीरे एक एकीकृत परविहन मंत्रालय की स्थापना करना है। यह एनडीए सरकार के स्लोगन 'नयूनतम सरकार और अधिकतम शासन' को अपनाने पर बल देता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर एक एकल एकीकृत (single unified) 'लॉजिस्टिक्स और एकीकृत परविहन नकियाय' वर्तमान प्रणाली की तुलना में लाभकारी सिधि होगा।
- इस परपिरेक्ष्य में केंद्र, राष्ट्रीय परविहन विकास नीति समितिकी रपिर्ट पर वचिार कर रहा है। इस समितिकी अध्यक्षता राकेश मोहन द्वारा की गई थी।
- इस रपिर्ट में यह भी कहा गया था कि इनमें से कुछ समेकित राष्ट्रीय एजेंसियों को संचार (अथवा समकक्ष) मंत्रालय के साथ भी जोड़ा जाएगा।
- इस रपिर्ट ने यह सुझाव दिया कि भारत को एक स्पष्ट अधदिश के माध्यम से बहुरूपी परविहन प्रणाली का वतिरण (जो भारत के बड़े लक्ष्यों में योगदान करती है जैसे-आर्थिक विकास, रोजगार का प्रसार, अवसरों का भौगोलिक प्रसार, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा) करने के लिये एक एकल एकीकृत मंत्रालय की आवश्यकता है।
- केंद्र सरकार 50,000 करोड़ से अधिक धनराशि का निवेश कर 35 बहुरूपी लॉजिस्टिक्स के निर्माण की भी योजना बना रही है।

नषिकर्ष

भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला और रसद से जोड़ने के लिये केंद्र सरकार ने पछिले माह ही संयुक्त राष्ट्र के टीआईआर सम्मेलन में भारत के प्रवेश को स्वीकृत प्रदान की थी। यह भारतीय व्यापारियों को क्षेत्र में सड़क अथवा बहुरूपी साधनों के माध्यम से वस्तुओं के आवागमन के लिये परेशानी मुक्त वैश्विक प्रणाली तक पहुँच बनाने में सहायता करेगा।